पंजाब राज्य व अन्य बगैरा

बनाम

सुप्रीत राजपाल व अन्य बगैरा

13 नवंबर, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सथाशिवम, जेजे.)

सेवा कानूनः

अंशकालिक व्याख्याता की सेवा का नियमितीकरण- उत्तरदाता-अंशकालिक व्याख्याताओं द्वारा रिट याचिका दायर की गई- उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारियों को नियमितीकरण के लिए उन पर विचार करने का निर्देश दिया गया- अपील पर, माना गया: मामले के विशिष्ट तथ्यों में, यह उचित होगा की उच्च न्यायालय हरगुरु प्रताप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में मामलों से नए सिरे से निपटए।, - इस प्रकार, मामला नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया।

इस अपीलों में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उत्पन्न हुआ वह यह था कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों उत्तरदाताओं-अंशकालिक व्याख्याता की सेवाओं को नियमित करने के लिए निर्देश दिया जो सही है, हालाँकि उन्होंने ऐसी कोई राहत नहीं मांगी थी।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि रिट याचिकाओं में प्रार्थना सेवाओं के नियमितीकरण के लिए नहीं थी और उनके द्वारा मांगी गई राहत अलग थी; और यह कि आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने विज्ञापन में दर्शाए गए और नियुक्ति की

शर्तों में उल्लिखित संविदात्मक खंड के डी-हॉर्स नियमितीकरण के लिए उत्तरदाता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

मामले के विशिष्ट तथ्यों पर, उच्च न्यायालय के लिए हरगुरु प्रताप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के निर्णयित मामले में जो कहा गया है, उसके आलोक में मामलों से नए सिरे से निपटना उचित होगा। मामला उच्च न्यायालय को नये सिरे से विचार हेतु भेजा जाता है। [1127-बी]

हरगुरु प्रताप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य आदि, सी. ए. 2003 का सं. 8745 (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7.11.2003 को निर्णय लिया गया), पर विश्वास किया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5165-5167/2007।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के सिविल रिट याचिका संख्या 20036/03, 3766/04 & 7500/04 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 2.12.2004 से।

कुलदीप सिंह, आर.के. पांडे, एच.एस. संधू, टी.पी. मिश्रा और अजय पाल अपीलार्थी के लिए।

प्रत्यर्थी के लिए उग्र शंकर प्रसाद और एस.के. सभरवाल।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों में चुनौती पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को दी गई है, जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट

याचिकाओं को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अंशकालिक व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था:

> "उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे विज्ञापन में दर्शाए गए संविदात्मक खंड के डी-हॉर्स याचिकाकर्ताओं को नियमित करने के लिए विचार करें और नियुक्ति की शर्तों में भी इसका उल्लेख किया जावे। यदि नियमित किया जाता है, तो उन्हें तदनुसार देय प्रारंभिक वेतन के साथ नियमित वेतनमान में रखे जाने पर भी विचार किया जाएगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया उत्तरदाताओं द्वारा इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर की जाएगी। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस तथ्य के कारण कि राज्य ने सुश्री मनिंदर कौर के मामले (उपरोक्त) में दिए गए फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की है, उसके परिणाम से विचार और याचिकाकर्ताओं को दी गई व दिए जाने योग्य राहत पर भी असर पड़ेगा। इस तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख संबंधित अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों में किया जा सकता है। ऐसे मामले जहां नियमितीकरण पहले ही किया जा चुका है को सरकार की पूर्वोक्त नीतियों या जैसा भी मामला हो, को तदनुसार लागू संबंधित वेतनमान में और कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक चरण में रखे जाने पर विचार किया जाएगा। शास्ती के संबंध में कोई आदेश नहीं दिए गए।"

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किए हैं कि रिट याचिकाएँ में सेवाओं के नियमितीकरण और राहत के लिए प्रार्थना नहीं थी उनके द्वारा मांगा गया अनुतोष आक्षेपित निर्णय से अलग था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों के

मामले में नियमितीकरण के लिए विज्ञापन और नियुक्तियों की शर्तों में उल्लेख संविदात्मक धारा पर विचार डी-हॉर्स करने का निर्देश दिया है

4. उत्तरदाताओं की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश जो कई सिविल अपीलों के समूह, यानी 2003 की सिविल अपील संख्या 8745 और अन्य अपील हरगुरु प्रताप सिंह और अन्य. बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य आदि निस्तारित 07.11.2003 का उल्लेख किया है में निम्नलिखित टिप्पणियों पर विशेष बल दिया गया:

> "हमने उच्च न्यायालय के फैसले और इस न्यायालय के समक्ष पेश किए गए अन्य अभिवचन को ध्यान से देखा है। यह स्पष्ट है कि हालांकि अपीलकर्ता नियमित नियुक्ति के हकदार नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वे न्यूनतम वेतनमान के हकदार नहीं होंगे और न ही उन्हें नियमित पदधारियों की नियुक्ति होने तक जारी नहीं रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एक तदर्थ व्यवस्था को दूसरी तदर्थ व्यवस्था द्वारा विस्थापित करना है, जो अनुभव प्राप्त करने वाले इन व्यक्तियों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है।, जो तदर्थ आधार पर नए सिरे से व्यक्तियों को नियुक्त करने के बजाय संबंधित कॉलेजों के लिए अधिक फायदेमंद और उपयोगी होगा। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश जो अपीलकर्ताओं के न्यूनतम वेतनमान और नियमित पदधारियों की नियुक्ति होने तक सेवा में बने रहने के दावे को अस्वीकार करता है को इस हद तक रद्द करते हैं। हम निर्देश देते हैं कि उन्हें नियमित

नियुक्ति होने तक न्यूनतम वेतनमान पर सेवा में जारी रखा जावे। अपीलें तदनुसार आंशिक रूप से स्वीकार की गई।"

6. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा जिस मामले पर भरोसा किया गया है उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि यह अंशकालिक व्याख्याताओं से संबंधित नहीं है और वास्तव में कुछ अन्य अंशकालिक नियुक्तियों से संबंधित है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उन मामलों में भी मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है।

7. मामले के विशिष्ट तथ्यों पर, हमें लगता है कि हरगुरु के मामले (उपरोक्त) में जो कहा गया है, उसके आलोक में उच्च न्यायालय के लिए मामलों को नए सिरे से निपटाना उचित होगा। मामलों को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाता है।

8. अपीलों को शास्ती के संबंध में बिना किसी आदेश के तदनुसार निस्तारित जाता है।

एसकेएस. अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रूपेंद्र चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।